bjpkamaljyoti@gmail.com संवत 2076 युगाब्द 5120 मूल्य : ₹10 अंक – 11, जनवरी प्रथम अंक 2020, कुल पृष्ठ – 32

वर्तमान कमल ज्योति

प्रदेश कार्यालय पर बैठक

बच्ची को अपने हाथों से खीर खिलाते हुए मा. मुख्यमंत्री जी

फर्रुखाबाद

कानपुर ग्रामीण व देहात

सिद्धार्थ नगर

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह

सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार

प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

संपादकीय

संक्रांति काल से आगे बढ़ता भारत

विश्व में कुल 190 से अधिक देश हैं। कुल 50 के लगभग विकसित देश हैं। करीब 20 देश अति विकसित श्रेणी में हैं। उनमें भी 7 देश अति-अति विकसित है। आज भी देश में कुछ लोग कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन मात्र 5 देशों ने बनाई और उनमें से एक हमारा देश हैं। अर्थात हमनें विकासशील देश होकर भी अति-अति विकसित देशों को पछाड़ दिया। वह भी कोई साधारण वैक्सीन निर्माण में नही बल्कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के वैक्सीन निर्माण में। सभी 5 देशों की वैक्सीन में भारत की वैक्सीन सबसे अधिक प्रभावी बतायी जा रही हैं। क्योंकि ये कोविड के नये स्ट्रेन पर भी कार्य करेगी। कुल 32 छोटे-बड़े देश भारत को वैक्सीन के लिए प्री ऑर्डर का प्रस्ताव रख चुके हैं। पूरी दुनिया में भारत और हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि के नाम का डंका बज रहा है। सम्पूर्ण विश्व भारत की और आशा भरी दृष्टि से टक-टकी लगाए देख रहा हैं।

इसलिए अपने देश पर.. अपने देश के नेतृत्व पर...अपने वैज्ञानिकों पर..हमको गर्व होता है।

कोरोना के संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश सबसे संयमित और कार्यगतिशीलता में आगे रहा। प्रदेश की यशस्वी सरकार ने हर मोर्चे पर आगे आकर प्रदेश की 23 करोड़ आम जन को बचाने में दिन-रात एक कर दिया। गरीबों को राशन वितरण में प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर रहा। कोरोना की उच्चतम स्थिति में भी उत्तर प्रदेश में सभी चीनी मिलों ने किसानों से उनके खेतों का एक-एक गन्ना खरीदा और जब तक किसानों का गन्ना समाप्त नही हो गया तब तक चीनी मिलों को पेराई सत्र चलता रहा है। रिकार्ड स्तर पर किसानों को उनके खातों में भुगतान भेजा गया और कोरोना काल में प्रदेश ने रिकार्ड स्तर पर खाद्यान्न का उत्पादन किया।

शायद इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश की रणनीति की सराहना की। आरबीआई द्वारा जारी स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी अन्य राज्यों की तुलना में कोरोनो वायरस संक्रमण की लहर में स्थिति को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सफल रहा। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने हर मोर्चे पर अच्छी तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए तय किए गए 9 मानदंडों में से 8 में यूपी ने पहला स्थान हासिल किया। स्टडी आफ स्टेट बजट की रिपोर्ट के अनुसार, चाहें कोरोना से पीड़ित रोगियों के लिए अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों या मास्क और वेंटिलेटर की व्यवस्था

हो, उत्तर प्रदेश ने सबसे तेज और प्रभावी तरीके से काम किया। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश भी शीर्ष पर रहा। यूपी ने कोरोना रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के बाद पहला स्थान हासिल किया। डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को गुजरात, तमिलनाडु और चेन्नई के बाद एन-95 मास्क देने में यूपी शीर्ष पर है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के मामले में यूपी के बाद 18 अन्य राज्य हैं।

ऐसे में जब आज कोरोनो का अंतिम तौर पर पराजित करने का अभियान अपने चरम पर आ चुका है। वैक्सीनेशन के हर चरण के लिए पूरा देश तैयार है। हर राज्यों में कोरोना वारियर्स को पहले चरण के टीकाकरण के लिए सेना अपने अभियान में जुट गई है। 16 जनवरी से इस मंगलाचरण के लिए जब वैक्सीनेशन आरंभ होगा तब भगवान भाष्कर मकर राशि में चक्रण करेंगे। वे उत्तरायण होकर धरा पर अपने अपने प्रकाश को तीव्र से तीव्रतर करेंगे। उस समय देश संक्रांतिकाल से उबरकार आगे बढ़ रहा होगा।

चूंकि गुरुवार बृहस्पति देव का दिन है। ज्योतिष ग्रंथों में इसे शुभ दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन उत्तरायण होना यानी सूर्य का राशि बदलना बहुत ही शुभ होता है। यह संक्रांति गुरुवार को पड़ रही है जिससे देश में महंगाई कम होने के आसार हैं। इस बार सूर्य के राशि बदलते ही मकर राशि में सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि होने से पंचग्रही योग बन गया है। ग्रहों की यह युति बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाने का संकेत है। मयूरचित्रकम् में कहा गया है कि- पंचग्रही घ्नन्ति चतुष्पदानां अर्थात् पंचग्रही योग पशुओं के लिये हानिकारक है।

इस वर्ष के मकर संक्रान्ति के सामूहिक फल पर विचार करें तो- लोगों की सेहत में सुधार होगा। महंगाई कम होगी। अन्य देशों से भारत के संबंध मजबूत होंगे। देश में अनाज भण्डारण बढ़ेगा। धार्मिक क्षेत्र, न्याय व शिक्षा क्षेत्रों में अति संघर्ष, असन्तोष और आन्दोलन प्रदर्शन होंगे। आन्दोलन, प्रदर्शन और विशेष विरोध होंगे। विश्व पटल पर भारत का प्रभाव बढ़ेगा। मकर संक्रान्ति का काल देवताओं की मध्यरात्रि का काल है और इसके बाद देवता अपने दिन की ओर उन्मुख होने लगते हैं। देवताओं के दिन होने से भारत का भाग्य भी बदल रहा है। देश हर ओर से आगे की जा रहा है। व्यापारिक सामाजिक और राजनीतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसिलए दिनोन्मुखत्वमेव दिनम कहकर बस अब आगे बढ़ते जाना है।

akatri.t@gmail.com

यू.पी. साहित छह राज्यों में लाइट हाउस परियोजना

लाइट हाउस परियोजनाओं ने देश में आवास निर्माण के क्षेत्र को नई दिशा दी : प्रधानमंत्री

- घर की चाबी गरिमा, आत्मविश्वास, सुरक्षित भविष्य, नई पहचान और विस्तार की संभावनाओं के द्वार : प्रधानमंत्री
- अब तक 2 करोड़ ग्रामीण आवास बनाए गए, ग्रामीण आवास बनाने की गति में इस वर्ष तेजी लाने के प्रयास जारी रहेंगे : प्रधानमंत्री

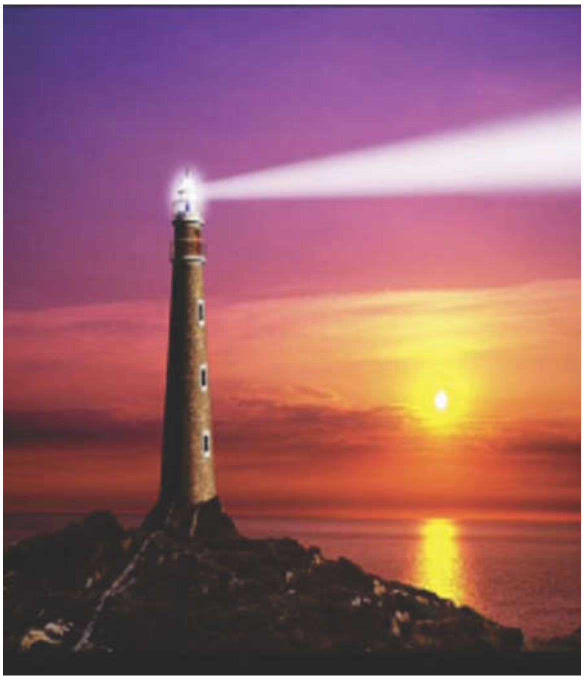

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी) के अंतर्गत छह राज्यों में छह स्थानों पर, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) की आधारशिला रखी। उन्होंने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स- इंडिया (आशा- इंडिया) के तहत विजेताओं की घोषणा की और प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार दिए। उन्होंने एनएवीएआरआईटीआईएच (भारतीय आवास के लिए नवीन, सस्ती, विधिमान्य, अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी) नाम के नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम भी जारी किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित थे।

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने, नए संकल्पों को साबित करने का दिन है और आज देश को गरीब, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई तकनीक मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन घरों को तकनीकी भाषा में लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहा जाता है लेकिन ये 6 परियोजनाएं वास्तव में लाइटहाउस की तरह हैं जो देश में आवास निर्माण के क्षेत्र को एक नई दिशा दिखा रही है।

प्रधानमंत्री ने इन लाइट हाउस परियोजनाओं को वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि एक समय में आवास योजनाएं केन्द्र सरकार की प्राथमिकता नहीं हुआ करती थीं, गृह निर्माण की बारीकियां और गुणवत्ता भी नहीं थी। आज, देश ने परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक अलग मार्ग और बेहतर तकनीक को अपनाते हुए, अलग दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने सरकारी मंत्रालयों के लिए बड़े और निष्क्रिय ढांचे की नहीं, बल्कि स्टार्टअप की तरह फिट होने वाले ढांचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने दुनिया भर से 50 से अधिक उन्नतिशील निर्माण कंपनियों की सक्रिय भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक चुनौती ने हमें नई तकनीक के साथ नया करने और विकास को बढ़ावा देने का अवसर दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी प्रक्रिया के अगले चरण में, विभिन्न स्थानों पर 6 लाइट हाउस परियोजनाओं का काम आज से शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और नवीन प्रक्रियाओं से बने होंगे और निर्माण के समय को कम करेंगे और गरीबों के लिए अधिक लचीले, किफायती और आरामदायक घर बनाएंगे। उन्होंने बताया कि इन लाइट हाउसों में निर्माण प्रौद्योगिकी में नवाचार हैं। उदाहरण के लिए इंदौर में परियोजना में ईंट और मोर्टार दीवारें नहीं होंगी, इसके बजाय वे पूर्वनिर्मित सैंडविच पैनल प्रणाली का उपयोग करेंगे। राजकोट में लाइट हाउसों को फ्रेंच तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा और सुरंग का उपयोग करके एक पत्थर की ठोस निर्माण तकनीक होगी। ये घर आपदाओं को झेलने में अधिक समर्थ होंगे। चेन्नई में, यूएस और फिनलैंड की

प्रौद्योगिकियां प्रीकास्ट कंक्रीट प्रणाली का उपयोग करेंगी, जिससे घर का निर्माण तेजी से और सस्ता होगा। जर्मनी की 3 डी निर्माण प्रणाली का उपयोग करके रांची में मकान बनाए जाएंगे। प्रत्येक कमरे को अलग से बनाया जाएगा और फिर पूरी संरचना को उसी तरह से जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक के खिलौनों को जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि अगरतला में स्टील के फ्रेमों के साथ न्यूजीलैंड की तकनीक का उपयोग करते हुए मकान बनाए जा रहे हैं जो भूकंप के बड़े जोखिम को झेल सकते हैं। कनाडा की प्रौद्योगिकी का उपयोग लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टर और पेंट की आवश्यकता नहीं होगी और तेजी से मकान बनाने के लिए पहले से तैयार की गई पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक स्थान पर 12 महीनों में हजारों घर बनाए जाएंगे जो इंक्यूबेशन केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे योजनाकार, वास्तुकार, इंजीनियर और छात्र नई तकनीक के साथ अध्ययन और प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने घोषणा की कि इसके साथ ही निर्माण क्षेत्र में नई तकनीक से संबंधित कौशल उन्नयन के लिए लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को घर के निर्माण में दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक और सामग्री मिल सके।

प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि देश के भीतर आधुनिक आवास प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आशा-इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से, 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक भारत में ही विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत पांच सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का भी चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों का सबसे बड़ा सपना उनका अपना घर होना है। लेकिन वर्षों से, लोग अपना घर होने को लेकर विश्वास खो रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वास अर्जित करने के बावजूद भी, उच्च कीमतों के कारण मांग कम हो गई है। लोगों ने भरोसा खो दिया है कि क्या वे किसी भी मुद्दे के मामले में कानूनी रूप से खड़े हो सकते हैं। बैंक की उच्च ब्याज दर और ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों ने भी घर का मालिक बनने की दिलचस्पी कम कर दी है। उन्होंने एक आम आदमी का विश्वास बहाल करने के लिए पिछले 6 वर्षों में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया कि उसके पास भी अपना घर हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत कम समय में लाखों घर बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में घर-मालिकों की स्थानीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार नवाचार और कार्यान्वयन दोनों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह एक पूर्ण पैकेज है क्योंकि प्रत्येक इकाई बिजली-पानी-गैस कनेक्शन से सुसज्जित है। लाभार्थियों के लिए जियो-टैगिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।

मध्यम वर्ग के लिए लाभ के बारे में बात करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि उन्हें होम लोन के ब्याज पर छूट मिल रही है। अधूरी आवास परियोजनाओं के लिए सृजित 25 हजार करोड़ रुपये के विशेष फंड से मध्यम वर्ग को भी मदद मिलेगी। रेरा जैसे उपायों ने घर के मालिकों का विश्वास वापस ला दिया है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनकी गाढ़ी कमाई के साथ कोई धोखा नहीं होगा। रेरा के तहत 60 हजार परियोजनाएं पंजीकृत हैं और हजारों शिकायतों का निवारण कानून के तहत किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर की चाबी प्राप्त करना न केवल एक आवास इकाई का कब्जा लेना है, बल्कि यह गरिमा, आत्मविश्वास, सुरक्षित भविष्य, नई पहचान और विस्तार की संभावनाओं के द्वार खोलता है। 'सभी के लिए आवास' (हाउसिंग फॉर ऑल) के लिए किए जा रहे चौतरफा कार्य करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी यानि अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीमों के दौरान शुरू की गई नई योजना का भी उल्लेख किया। सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए आने वाले श्रमिकों को उचित किराए के साथ आवास प्रदान करने के लिए उद्योग और अन्य निवेशकों के साथ काम कर रही है। उनके आवास की स्थिति अक्सर गंदी और गरिमारहित होती है। श्री मोदी ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें उनके कार्यस्थल के आसपास के क्षेत्र में उचित किराए पर आवास प्रदान किए जाए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे कामकाजी मित्र सम्मान के साथ रहें।

प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट क्षेत्र की मदद के लिए हाल ही में किए गए उपायों को भी याद किया। सस्ते मकानों पर कर में 8 से 1 प्रतिशत की कटौती, जीएसटी में 12 से 5 प्रतिशत की कटौती जैसे उपाय, सस्ते ऋण के लिए इस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता देने से निर्माण की अनुमति से हमारी रैंकिंग 185 से 27 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2000 से अधिक शहरों में निर्माण प्रक्रिया की अनुमति ऑनलाइन ली गई है।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि ग्रामीण भारत में 2 करोड़ से अधिक आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है। इस वर्ष ग्रामीण आवास की गति में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा।

100वीं किसान रेल

खेती के क्षेत्र में निजी निवेश से किसानों को मदद मिलेगी : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा देश के किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच 4 महीनों में 100वीं किसान रेलचलाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सेवा कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आएगी और देश की कोल्ड सप्लाई चेन को सशक्त करेगी। उन्होंने आगे कहा कि किसान रेल के माध्यम से कृषि उत्पादों की ढुलाई में कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है। यहां तक कि इससे छोटे से छोटा उत्पादक भी कम लागत में बड़े बाजारों तक उपयुक्त ढंग से पहुंच सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल परियोजना न सिर्फ किसानों को सेवा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे हमारे किसान नई संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए तेजी से तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि किसान अब अपने उत्पाद न सिर्फ अपने राज्य में बेच सकते हैं बल्कि किसान रेल और कृषि उड़ान सेवाओं के माध्यम से भी अपने उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं, जिनकी कृषि क्षेत्र में बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने आगे कहा कि किसान रेल सचल शीत गृह (मोबाइल कोल्ड स्टोरेज) की व्यवस्था है जो फल, सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्द खराब होने वाले उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाती है वह भी पूर्ण सुरक्षा के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूं तो भारत के पास आजादी के पहले से भी रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है, कोल्ड स्टोरेज तकनीक भी पहले से थी लेकिन किसान रेल के माध्यम से इस समय इसे सशक्त बनाया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल जैसी सुविधाओं ने पश्चिम बंगाल के लाखों किसानों को एक बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है। यह सुविधा किसानों के साथ-साथ स्थानीय छोटे व्यवसायियों के लिए भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में मौजूद विशेषज्ञों और दुनिया के अन्य देशों के अनुभवों तथा नई प्रौद्योगिकियों का भारतीय कृषि क्षेत्र में क्रियान्वयन हो रहा है।

जल्द खराब होने वाले 'कृषि उत्पादों का भंडारण केंद्र', रेलवे स्टेशनों के आसपास निर्मित किए जा रहे हैं,जहां किसान अपने उत्पादों का संग्रहण कर सकते हैं। यह प्रयास ज्यादा से ज्यादा संख्या में फलों और सब्जियों को ग्राहकों तक पहुंचाने के क्रम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यकता से अधिक उत्पाद होने की स्थिति में जूस,आचार,चिप्स इत्यादि कोछोटे निर्माताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार की प्राथमिकता संग्रहण से जुड़े ढांचे के निर्माण और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन संबंधित प्रसंस्करण उद्योग से हैं। उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क,कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजनाओं के अंतर्गत 6500 परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत स्वीकृति दे दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपयेकी राशि को मंजूरी प्रदानकीगई है।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार के इस प्रयास को सफल बनाने में ग्रामीण लोगों, किसानों और युवाओं का सहयोग तथा सहभागिता रही है। कृषि उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) और सहकारी समूह जैसे महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि व्यवसाय और कृषि बुनियादी ढांचे में प्राथमिकता दी गई है। हाल के कृषि सुधारों से कृषि व्यवसाय और इन समूहों को व्यापक पैमाने पर लाभ पहुंचेगा और इन्हें बड़ा विस्तार मिलेगा। इन समूहों को मदद करने के सरकार के प्रयास में निजी निवेश से सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कृषि और किसानों को सशक्त करने के मार्ग पर हम पूर्ण समर्पण भाव से आगे बढ़ते रहेंगे।

खुर्जा खंड तथा पूर्वी समर्पित मालढुलाई गलियारा

इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू भाउपुर-न्यू खुर्जा खंड तथा पूर्वी समर्पित मालढुलाई गरियारे के संचालन नियंत्रण केन्द्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री, श्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आधुनिक रेल अवसंरचना परियोजना को धरातल पर लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब खुर्जा भाउपुर मालढुलाई गलियारे में पहली मालगाड़ी चलती है तो हम आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केन्द्र आधुनिक नियंत्रण केंद्रों में से एक है, जो नए भारत की नई ताकत का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि जब भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले छह वर्षों से आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राजमार्गों, रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग और आई-वे के पांच पहियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पूर्वी समर्पित मालढुलाई गलियारे के एक बड़े हिस्से का उद्घाटन इस दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग, व्यवसायी, किसान या उपभोक्ता, हर कोई इस समर्पित मालढुलाई गलियारे से लाभान्वित होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मालढुलाई गलियारा पूर्वी भारत को बढ़ावा देगा, जो औद्योगिक रूप से पीछे रह गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 60 प्रतिशत गलियारा यूपी में पड़ता है। यह यूपी की ओर बहुत सारे उद्योगों को आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि इस समर्पित मालढुलाई गलियारे के कारण किसान रेल को फायदा होगा। किसान अपनी उपज को रेलगाड़ी के माध्यम से देश भर के किसी भी बड़े बाजार में सुरक्षित और कम कीमत पर भेज सकते हैं। अब इस मालढुलाई गलियारे के माध्यम से उनके उत्पाद और भी तेजी से पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान रेल के कारण बहुत सारे भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो गई है।

प्रधानमंत्री ने इन समर्पित मालढुलाई गलियारों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि

जनसंख्या बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था बढ़ी और मालढुलाई की मांग कई गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि चूंकि यात्री रेलगाड़ियां और मालगाड़ियां दोनों एक ही ट्रैक पर चलती हैं, इसलिए मालगाड़ी की गति धीमी है। उन्होंने कहा कि जब मालगाड़ी की गति धीमी होती है और रुकावट होती है, तो जाहिर है कि परिवहन की लागत अधिक होगी। उन्होंने कहा कि महंगा होने के कारण हमारे उत्पाद देश के बाजारों के साथ-साथ विदेशों में भी प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बदलने के लिए समर्पित मालढुलाई गलियारे की योजना बनाई गई थी। प्रारंभ में 2 समर्पित मालढुलाई गलियारे की योजना बनाई गई थी। पूर्वी लुधियाना से दनकुनी के लिए समर्पित मालढुलाई गलियारे में कोयला खदान, थर्मल पावर प्लांट और औद्योगिक शहर हैं। इनके लिए फीडर रूट भी बनाए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से दादरी तक पश्चिमी समर्पित मालढुलाई गलियारा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के समर्पित मालढुलाई गलियारों के बल पर यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में देरी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

मालगाड़ी की इस गति के कारण मालढुलाई की मात्रा को दोगुना करना संभव होगा। उन्होंने कहा कि जब मालगाड़ियां समय पर पहुंचेंगी तो हमारे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की लागत सस्ती होगी। जब हमारा माल सस्ता होगा, तो इससे हमारे निर्यातों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर माहौल बनेगा, कारोबारी सुगमता बढ़ेगी तथा भारत निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बन जाएगा एवं स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री ने समर्पित मालढुलाई गलियारे के क्रियान्वयन में अतीत में हुई अत्यधिक देरी पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक एक किलोमीटर भी पटरी नहीं बिछायी जा सकी। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार के गठन के बाद, निरंतर निगरानी और हितधारकों के साथ बैठक के परिणामस्वरूप लगभग 1100 किलोमीटर का काम अगले कुछ महीनों में पूरा हो गया। उन्होंने पिछले शासन की मानसिकता की आलोचना की, जिसने पटरियों को बढ़ाने के बजाय रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया था। इस दौरान रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर ज्यादा निवेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अलग रेल बजट के उन्मूलन के साथ इसमें बदलाव किया गया था और रेल ट्रैक पर निवेश किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेल नेटवर्क के चौड़ीकरण तथा विद्युतीकरण एवं मानव-रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे में हर स्तर पर सुधार किए गए हैं, जैसे- स्वच्छता, बेहतर भोजन, पेय एवं अन्य सुविधाएं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार रेलवे से संबंधित विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाना एक बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि भारत अब आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण करने के साथ-साथ उनका निर्यात भी कर रहा है। वाराणसी विद्युत इंजनों के निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, रायबरेली में निर्मित रेल कोच अब विदेशों में निर्यात किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास को राजनीति से दूर रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश का बुनियादी ढांचा कई पीढ़ियों को लाभ पहुंचाने वाला मिशन होना चाहिए, न कि 5 साल की राजनीति। यदि राजनीतिक दलों को प्रतिस्पर्धा करनी है, तो बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, गति और पैमाने पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।

उन्होंने प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की सलाह दी। उन्होंने आग्रह किया कि हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकार की अभिव्यक्ति करते हुए राष्ट्र के प्रति एक दायित्व को नहीं भूलना चाहिए।

विरासत में मिली चुनौतियां

वर्ष 2021 की उम्मीदों भरी तस्वीर

आने वाले साल में मुश्किलें कम नहीं हैं और अर्थव्यवस्था को पटरी लाने के लिए स्पष्ट और ठोस नीतियों की जरूरत है। बीते वर्ष पर नजर डालें तो पाते हैं कि फरवरी के बाद जैसे-जैसे देश पर कोरोना महामारी का साया गहराता गया, वैसे-वैसे देश में अकल्पनीय आर्थिक निराशा और बेरोजगारी का दौर भी बढ़ता गया।

अब नए वर्ष 2021 को बीते वर्ष से कोविड-19 की आर्थिक चुनौतियां तो विरासत में मिली हैं। फिर भी जिस तरह सरकार ने गुजरे साल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला किया, उससे ढहती हुई अर्थव्यवस्था को बचा पाने में कामयाबी मिली है।

कोरोना संकट से उद्योग कारोबार की बढ़ती मुश्किलों के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी को कोरोना को प्राकृतिक आपदा का एलान कर दिया था। चूंकि भारतीय दवा उद्योग, वाहन उद्योग, रसायन उद्योग, खिलौना कारोबार और बिजली व इलैक्ट्रॉनिक्स कारोबार प्रमुख रूप से चीन से आयातित कच्चे माल व वस्तुओं पर आधारित रहे हैं, ऐसे में इनकी आपूर्ति रुकने से ये उद्योग-कारोबार गंभीर संकट में फंस गए और इनमें से ज्यादातर के सामने बंद होने की नौबत खड़ी हो गई। कई तो बंद भी हो गए। खासतौर से जो सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योग (एमएसएमई) पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे, कोरोना काल में पूर्णबंदी के कारण इन उद्यमियों के सामने गंभीर संकट खड़े हो गए। उत्पादन बंद हो गया, कर्मचारियों को वेतन से लेकर रोजमर्रा के खर्च तक के लाले पड़ गए। लोगों के सामने नौकरी और रोजगार बचाना बड़ी चुनौती बन गई।

खासतौर से देश के करीब पैंतालीस करोड़ कार्यबल में से असंगठित क्षेत्र के नब्बे फीसद श्रमिकों और कर्मचारियों का काम बंद हो गया। लाखों श्रमिक शहर छोड़ कर अपने-अपने गांवों को लौट गए। यह वह वर्ग था जिसके पास सामाजिक सुरक्षा की कोई बड़ी छतरी नहीं थी।

कोविड-1 9 के संकट से चरमराती देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत वर्ष 2020 में मार्च से नवंबर के बीच सरकार ने एक के बाद एक कुल 29.87 लाख करोड़ की राहत पैकेजों का एलान किया।

इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान- एक के तहत 11,02,650 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1,92,800 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 82911 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत अभियान-दो के तहत 73,000 करोड़ रुपए, आरबीआइ के उपायों से राहत के तहत 12,71,200 करोड़ रुपए और आत्मनिर्भर भारत अभियान- तीन के तहत 2.65 लाख करोड़ की राहत शामिल थे।

तीसरे आर्थिक पैकेज में दो तरह की राहतें थीं। एक, दस उद्योग क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना और दूसरी, अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए रोजगार सृजन, ऋण गारंटी समर्थन स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास, रियल एस्टेट कंपनियों को कर राहत, ढांचागत क्षेत्र में पूंजी निवेश की सरलता, किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी, ग्रामीण विकास तथा निर्यात सेक्टर को राहत देने के 1.19 लाख करोड़ रुपए के लिए लाभपूर्ण प्रावधान।

इन विभिन्न राहतों से तेजी से गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बल मिला है। यह बात महत्त्वपूर्ण रही कि जून के बाद अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की रणनीति के साथ राजकोषीय और नीतिगत कदमों का अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ा।

हालांकि देश महामारी से नहीं उबरा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। कोरोना काल में सरकार को उन श्रम, कृषि, कारोबार और अन्य सुधारों को आगे बढ़ाने का भी मौका मिल गया जो दशकों से लंबित थे।

यदि हम दिसंबर 2020 तक के विभिन्न औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के आंकड़ों का मूल्यांकन करें, तो पाते हैं कि पूर्णबंदी की चुनौतियों के बाद दिसंबर तक देश के वाहन उद्योग, बिजली क्षेत्र, रेलवे, माल ढुलाई आदि में सुधार हुआ है। इतना ही नहीं दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं, सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन कलपुर्जा, दवा उद्योग, इस्पात और सीमेंट आदि क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर दिखा।

सूचना तकनीक (आइटी) क्षेत्र की बड़ी कंपनियों की ओर से भी सकारात्मक अनुमान देखने को मिले। सेवा कर (जीएसटी) संग्रह दिसंबर में बढ़ा हुआ दिखाई दिया। शेयर बाजार में भी तेजी का रुख रहा। इसी तरह देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी दिसंबर में 581 अरब डॉलर से भी ऊपर निकल गया।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले साल देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में आई भारी गिरावट को पाटने में विनिर्माण क्षेत्र ने बड़ा सहारा दिया। पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 39.3 फीसद की गिरावट आई थी, जबकि दूसरी तिमाही में इसमें 0.6 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि एवं सहायक गतिविधियों की विकास दर दूसरी तिमाही के दौरान आशाजनक रही।

खासतौर से खरीफ उत्पादन से संबंधित अनुमान अच्छे संकेत देने वाले रहे। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन 14.45 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर छूने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2019-20 के उत्पादन से 0.80 फीसद अधिक है। दलहन उत्पादन करीब 93.1 लाख टन अनुमानित है, जो 2019-20 की तुलना में करीब इक्कीस फीसद अधिक है। इसी तरह तिलहन का उत्पादन 2.57 करोड़ टन अनुमानित है, जो 2019-20 की तुलना में 15.28 फीसद अधिक है।

एशियाई विकास बैंक सहित विभिन्न वैश्विक संगठनों के मुताबिक कोविड-19 से जंग में भारत के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था पर जो भी प्रभाव पड़ा, वह अन्य देशों की तुलना में कम ही रहा। कोरोना महामारी के बीच भारत ने आपदा को अवसर में भी बदला है।

ऐसे में वर्ष 2021 की तस्वीर उम्मीदों भरी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में गिरावट तो आएगी, लेकिन भारत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए जिस तेजी से सुधार के कदम उठाए हैं, उससे आगामी वित्तीय वर्ष में भारत 8.8 फीसद की विकास दर हासिल करने की संभावनाओं वाला देश बन गया है। बस जरूरत है तो इस बात की कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल हो और जरूरतमंदों तक इनका लाभ पहुंचे।

अरुण कान्त त्रिपाठी

भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक

नि:संदेह 2021 में भारत में एफडीआइ बढऩे का सुकूनभरा परिदृश्य दिखाई दे रहा है। नया वर्ष 2021 देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) बढऩे की संभावनाओं के शुभ संकेत लेकर आया है। हाल में संयुक्त राष्ट्र आॢथक एवं सामाजिक परिषद द्वारा जारी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एफडीआइ के रुझान और परिदृश्य 2020-21 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन गई है। बीते दिनों उद्योग संगठन एसोचैम के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना आपदा के बीच देश में बड़े ऐतिहासिक आॢथक सुधार हुए हैं और उनसे भारत में विदेशी निवेश बढऩा लगा है। अब निवेशक 'भारत क्यों की जगह 'भारत ही क्यों नहीं कहने लगे हैं।

निश्चित रूप से बीते वर्ष में कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की बुनियाद पर आधारित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 29.87 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से जिस तरह अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है, उससे विदेशी निवेश प्रवाह बढऩे लगा है। सरकार ने पिछले छह वर्षों में उद्योग-कारोबार को आसान बनाने के लिए कई ऐतिहासिक सुधार भी किए हैं। टैक्स रिफॉर्म हुए हैं। जीएसटी लागू हुआ है। कॉरपोरेट कर में बड़ी कमी की गई है। साथ ही बड़े आयकर सुधार लागू हुए हैं। देश में आधार बायोमीट्रिक परियोजना, कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुधार और रेलवे, बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी

विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया गया है। इनसे भी एफडीआइ प्रवाह बढ़ा है। प्रवासी भारतीयों को घरेलू निवेशक के रूप में अनुमति दिए जाने से भी भारत एफडीआइ के लिए और अधिक आकर्षक देश बन गया है।

इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक एफडीआइ की अनुमति दी है। इसके साथ ही सरकार ने रक्षा, निर्माण क्षेत्र के विकास, बीमा, बिजली क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, पेंशन, अन्यब वित्तीय सेवाओं, प्रसारण, नागरिक उड्डयन, फार्मास्युटिकल्स, ट्रेडिंग जैसे कई क्षेत्रों में एफडीआइ संबंधी नीतिगत सुधार लागू किए हैं। केंद्र सरकार विभिन्न श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में तब्दील करने की महत्वाकांक्षी योजना को आकार देने में सफल रही है। ऑनलाइन ईएसआइसी और ईपीएफओ पंजीकरण जैसे कदमों से कारोबारी माहौल को और भी बेहतर किया गया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत देश में कारोबार को गति देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। निवेश और विनिवेश के नियमों में परिवर्तन भी किए गए हैं। इनसे भी एफडीआइ बढा है। देश में तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए भी विदेशी निवेशक आकृषत हुए हैं। देश के नवाचार में आगे बढऩे से भी एफडीआइ बढ़ा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत चार पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। कोविड-19 के कारण चीन के प्रति बढ़ती हुई नकारात्मकता और भारत की सकारात्मक छवि के कारण भी भारत में एफडीआइ प्रवाह बढ़ा है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के आंकड़ों के अनुसार भारत में एफडीआइ चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 15 प्रतिशत बढ़कर 30 अरब डॉलर हो गया। पिछले वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के दौरान एफडीआइ 26 अरब डॉलर रहा था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन (अंकटाड) की वैश्विक निवेश रिपोर्ट-2020 के मुताबिक भारत 2019 में सबसे अधिक एफडीआइ आकृषत करने वाले देशों की सूची में नौवें स्थान पर रहा। वर्ष 2018 में भारत इस सूची में 12वें स्थान पर था। यह बात महत्वपूर्ण है कि देश में एफडीआइ बढऩे के साथ-साथ एफडीआइ वाले क्षेत्रों का भी विस्तार होता गया है। डीपीआइआइटी के मुताबिक 2019-20 के दौरान 49.97 अरब डॉलर के कुल निवेश में से सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 7.85 अरब डॉलर का एफडीआइ आया।

जिन अन्य प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआइ आया, उनमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में 7.67 अरब डॉलर, व्यापार क्षेत्र में 4.57 अरब डॉलर, दूरसंचार क्षेत्र में 4.44 अरब डॉलर, वाहन क्षेत्र में 2.82 अरब डॉलर, निर्माण क्षेत्र में दो अरब डॉलर और रसायन क्षेत्र में एक अरब डॉलर का एफडीआइ प्रमुख है। यदि हम देश में एफडीआइ प्रवाह की दृष्टि से विभिन्न देशों के योगदान को देखें तो पाते हैं कि वर्ष 2019-20 में सिंगापुर से सर्वाधिक 14.67 अरब डॉलर का एफडीआइ आया। यह लगातार दूसरा वित्त वर्ष है जब भारत में सर्वाधिक एफडीआइ सिंगापुर के रास्ते से आया। इसके अलावा मॉरीशस से 8.24 अरब डॉलर, नीदरलैंड से 6.5 अरब डॉलर, अमेरिका से 4.22 अरब डॉलर, केमेन द्वीप से 3.7 अरब डॉलर, जापान से 3.22 अरब डॉलर, फ्रांस से 1.89 अरब डॉलर, ब्रिटेन से 1.42 अरब डॉलर, साइप्रस से 87.9 करोड़ डॉलर और जर्मनी से 48.8 करोड़ डॉलर का एफडीआइ आया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) और ईवाइ के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में आर्थिक सुधार, बाजार की क्षमता, कुशल श्रमबल और राजनीतिक स्थिरता ऐसे प्रमुख कारण हैं जो भारत को विदेशी निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बनाते हैं।

(अरुण कान्त त्रिपाठी)

जन्म दिन 12 जनवरी पर विशेष

उत्तराखंड में ही विवेकानंद को मिला वेदों का सार्वभौमिक सत्य

कहते हैं साधु और पानी बहता ही अच्छा, दोनों को एक जगह पर नहीं टिकना चाहिए, उससे उनमें मल नहीं आता। 1890 में जब स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद ने उन्हें केदारनाथ और बद्रीनाथ तीर्थ स्थलों के बारे में बताया और उनसे अपने हिमालय में जाकर तपस्या के अनुभव साझा किए, तो स्वामी विवेकानंद ने निश्चय किया कि वे भी हिमालय जाएंगे।

उन्होंने 6 जुलाई को स्वामी शारदानंद को पत्र में लिखा जैसे ही मेरे पास कुछ किराया जमा हो जाएगा तो मैं अल्मोड़ा जाऊंगा और गढ़वाल में गंगा के किनारे किसी जगह समाधि लगाऊंगा। हिमालय जाने के लिए काफी समय से मेरा मन तड़प रहा है।

15 जुलाई को उन्होंने पुन: लिखा कि भविष्य के लिए कुछ मेरी योजनाएं हैं जिन्हें अभी मैं साझा नहीं कर सकता। अपनी हिमालय यात्रा से पहले स्वामी विवेकानंद शारदा मां के पास आज्ञा लेने गए और उनसे कहा कि वे तब तक नहीं लौटेंगे जब तक परम तत्व को नहीं पा लेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था जब तक कि मैं उस स्थिति को ना प्राप्त कर लूं कि मेरे छूने मात्र से व्यक्ति का रूपांतरण हो जाए, तब तक मैं वहां से नहीं लौटूंगा। हिमालय में एकांत में साधना कर उन्होंने यह प्राप्त किया।

जुलाई 1890 में वे अपने गुरुभाई स्वामी अखंडानंद के साथ, सब चिंताओं से मुक्त हो हृदय में असीम आनंद लेकर गंगा के किनारे पैदल हिमालय की तरफ बढ़े। पेड़ों के नीचे सोना और भिक्षा पर रहना ही उनकी दिनचर्या थी। विवेकानंद ने लिखा है कि उत्तराखंड में ही वेदों का सार्वभौमिक सत्य उजागर हुआ।

यह हमारे पूर्वजों की धरती है जहां मां पार्वती का आविर्भाव हुआ था। वे चाहते थे कि हिमालय में ऐसी शांत जगह स्थापित की जाए, जहां साधक अपनी साधना कर सके। उन्होंने एक जगह लिखा यह पर्वत शृंखलाएं हमारे जाति की स्वर्ण स्मृतियों से जुड़ी है।

अगर इन हिमालय शृंखलाओं को आध्यात्मिक भारत के इतिहास से निकाल दिया जाए, तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए, यहां पर ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां से ना केवल समाज के उत्थान के क्रियाकलाप हो सकें बल्कि वह ध्यान साधना का भी केंद्र हो।

कुमाऊं की यात्रा करते हुए विवेकानंद काकडी घाट पर आए जो कोसी और सवाल नदियों का संगम है और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान साधना की । समाधि से उठ चेतनता में आने के बाद उन्होंने स्वामी अखंडानंद से साझा किया, मैं अपने जीवन के कुछ महान क्षणों के बीच से गुजरा। इस पीपल के पेड़ के नीचे जीवन का बहुत बड़े रहस्य का समाधान हुआ।

मैंने व्यष्टि और समष्टि का एकाकार अनुभव किया। इस देह रूपी पिंड में वह सभी कुछ है जो बाहर ब्रह्मांड में अभिव्यक्त है। मैंने पूरा ब्रह्मांड एक अणु में पाया। वह पूरा दिन स्वामी उच्च भाव अवस्था में रहे, उन्होंने बांग्ला में अपने भाव की अभिव्यक्ति की -यह पिंड और ब्रह्मांड एक ही सतह पर बने हैं। जिस तरह जीवात्मा जागृत शरीर में कैद है उसी तरह परमात्मा प्रकृति में। दोनों एक ही हैं सिर्फ शांत मन से ही इन दोनों में का भेद जाना जा सकता है।

अगस्त के अंत तक विवेकानंद अखंडानंद के साथ में अल्मोड़ा पहुंचे कुछ देर वहां रहने के बाद भी गढ़वाल हिमालय गए। भयंकर सर्दी के कारण स्वामी अखंडानंद का स्वास्थ्य बिगड़ा इसलिए वे दोनों टिहरी आ गए।

वहां टिहरी के दीवान रघुनाथ भट्टाचार्य को जब पता चला, तो उन्होंने स्वामी जी की सेवा सुश्रुषा के लिए इंतजाम किया। जब भी स्वामी जी ध्यान साधना के लिए एकांत में समय बिताना चाहते थे तो परिस्थिति वश उनको रुकना पड़ जाता था। यहां भी गणेश प्रयाग में उनके रहने का इंतजाम किया गया किंतु स्वामी अखंडानंद को ब्रोंकाइटिस हो गया, जिस कारण स्वामी विवेकानंद अंतत: देहरादून आ गए।

देहरादून में स्थानीय शिव मंदिर के पास में एक पानी की बारी थी, जहां किनारे पर कुछ साधुओं के लिए कुटिया बनी थी। वहीं पर स्वामी तुरियानंद तपस्या कर रहे थे, वे विवेकानंद के गुरु भाई थे । एक दिन विवेकानंद अंबिका देवी के मंदिर में गए और जब वह वहां से लौट रहे थे तो तुरियानंद से उनकी भेंट हो गई। फिर कुछ समय आनंद में दोनों गुरु भाई ने बिताया।

स्वामी विवेकानंद की हरिद्वार को महत्त्वपूर्ण दिन है जिसके लिए संसार सदा ऋणी रहेगा। स्वामी जी ने अनुभव किया था कि साधु जो केवल भिक्षा पर रहते हैं उनके अस्वस्थ होने पर उनकी देखरेख का कोई इंतजाम नहीं है।

उन्होंने अपने शिष्यों निश्चलानंद और कल्याणानंद को आदेश दिया कि वे एक चिकित्सा केंद्र की शुरूआत करें और 1901 में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की स्थापना कनखल में एक छोटे से कमरे में की गई और आज यह 200 बिस्तरों का अस्पताल सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और यहां पर आज भी साधुओं की और गरीब व्यक्तियों की निशुल्क चिकित्सा की जाती है।

हाल ही में यहां पर डायलिसिस सेंटर की भी सुविधा शुरू हुई है। इस सेवाश्रम में जीव सेवा ही ईश्वर सेवा के सिद्धांत को यहां के कर्म योगी साधु प्रतिपादित कर रहे हैं।

अर्धकुम्भ पर विशेष संन्यास और अखाड़े:

दशनामी संन्यासी अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर परंपरा

दशनामी परंपरा के सात अखाड़े तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा ,तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचदशनाम अग्नि अखाड़ा हैं। इनमें छह अखाड़े दस नाम नागा संन्यासी है जबकि सातवां श्री पंच दशनाम अग्नि अखाड़ा नागा संन्यासियों का नहीं बल्कि ब्रह्मचारी परंपरा का निर्वहन करता है।

आज से सैकड़ों साल पहले दशनामी संन्यास परंपरा के अखाड़ों को आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों शृंगेरी मठ, जोशीमठ, गोवर्धन मठ तथा शारदामठ के शंकराचार्य संन्यास दीक्षा दिया करते थे। परंतु कुछ मठों में मठ के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद हो गया।

इसके बाद सातों दशनाम संन्यासी अखाड़ों ने अपने-अपने अलग आचार्य महामंडलेश्वर के पदों को सृजित करने का करने का निर्णय लिया और इसी के साथ दशनाम संन्यासी अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर की परंपरा शुरू हुई।

आचार्य महामंडलेश्वर की नियुक्ति दशनामी संन्यासी परंपरा के अखाड़ों के रमता पंचों और श्री महंतों को होता है और अखाड़ों के रमता पंच और श्री महंत आचार्य महामंडलेश्वर को पद से हटाने का अधिकार भी रखते हैं। भले ही आचार्य महामंडलेश्वर का पद अखाड़ों में सर्वोपरि माना जाता है परंतु यह पद सीमित अधिकारों तक ही है।

आचार्य महामंडलेश्वर संन्यास दीक्षा देने तक ही सीमित है और आचार्य महामंडलेश्वर को अखाड़ों की प्रशासनिक व्यवस्था में दखलदांजी करने का कोई अधिकार नहीं है।

अखाड़ों के श्री महंतों को ही अखाड़ों की प्रशासनिक व्यवस्था करने का अधिकार है। अखाड़ों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति अखाड़ों के श्री महंतों और रमता पंचों में समाहित होती है और आचार्य महामंडलेश्वर का पद सर्वोच्च होते हुए भी केवल सुशोभित मात्र है।

दशनामी सन्यासी परंपरा के अखाड़ों के सरस्वती, गिरि, पुरी, वन, भारती, तीर्थ, सागर,अरण्य, पर्वत वर्ग होते हैं और जो नागा संन्यासी गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हैं वे गोस्वामी माने जाते हैं। इन दशनामी गोस्वामियों को आदि जगतगुरु शंकराचार्य का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है।

श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा के सचिव महंत रवींद्र पुरी महाराज का कहना है कि आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त

करने और उन्हें हटाने का अधिकार अखाड़ों के श्री महंतों और रमता पंचों को है जो चारों वेदों और उपनिषदों का का प्रकांड विद्वान होगा वही आचार्य महामंडलेश्वर पद पर सुशोभित होता है। आचार्य महामंडलेश्वर संन्यास दीक्षा प्रदान करते हैं।

संन्यास लेने वाले पात्र को अपना विजयाहोम संस्कार यानी अपनी तीन पीढ़ियों का श्राद्ध और अपना स्वयं का श्राद्ध करना होता है और शिखा सूत्र का त्याग करना पड़ता है और इससे इस तरह से संन्यासी भूत यानि अवशेष का रूप होता है।

आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा दक्षिण में शृंगेरी मठ उत्तर में जोशीमठ, पूर्व में गोवर्धन मठ तथा पश्चिम में शारदामठ की स्थापना की गई थी इन चारों मठों के अलग-अलग आचार्य आचार्य हस्तामलक, त्रोटकाचार्य, पद्मपादाचार्य और स्वरूपाचार्य माने जाते हैं और इनकी विभिन्न परंपराओं के ही साथ पुरी, भारती, सरस्वती, गिरि पर्वत, अरण्य, तीर्थ, आश्रम जैसे दशनामों के रूप में जुड़े होते हैं।

इन चारों में से शृंगेरी मठ का क्षेत्र दक्षिण भारत के आंध्र, कर्नाटक, केरल राज्यों तक फैला हुआ है। इसका तीर्थस्थान रामेश्वरम है और इसका वेद यजुर्वेद है। महावाक्य अहं ब्रह्मास्मि है, गोत्र भूरिवर है और इसके ब्रह्मचारी चैतन्य होते हैं। दूसरी ओर उत्तर दिशा में हिमालय क्षेत्र में स्थित बदरीधाम में जोशी मठ क्षेत्र उत्तर के कुरु, पांचाल, कश्मीर, कंबोज और तिब्बत का क्षेत्र शामिल है।

इसका तीर्थ स्थल बदरीनाथ धाम है और इनका वेद अथर्ववेद है तथा महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म है जबकि गोत्र आनंदवर है इस मठ के ब्रह्मचारी आनंद कहलाते हैं। भारत की पूर्व दिशा की और गोवर्धनमठ का क्षेत्र अंग, वंग, कलिंग, मगध, उत्कल तक फैला हुआ है। इस मठ का तीर्थ पुरी है।

जबकि इसका वेद ऋग्वेद है और महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्म है। गोत्र भोगवर है तथा इस मठ के ब्रह्मचारी प्रकाश नाम से संबोधित किए जाते हैं। चौथा और आखिरी मठ पश्चिम दिशा में शारदामठ है जिसका क्षेत्र सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र तक है। इसका वेद सामवेद है।

महावाक्य तत्वमसि है जबकि गोत्र कीटवर है तथा इसके ब्रह्मचारी स्वरूप कहलाए जाते हैं। दशनामी संन्यासी परंपरा के अखाड़ों की 52 मढ़ियां होती हैं जिनमें से 27 गिरियों की, 16 पुरियों की, 4 भारतीयों की, 4 वनों की तथा 1 लामा की कही जाती है जो तिब्बत में स्थित है । बाकी सभी भारत में स्थापित है। ये 52 मढ़ियां देश में स्थित विभिन्न 52 शक्तिपीठों की परंपरा के अनुसार ही स्थापित हैं और तीर्थों, आश्रमों, सरस्वतियों तथा भारतीयों में से आधे साढ़े तीन दंडी और शेष छह गोसाई कहे जाते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सहायता को दी मंजूरी

इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों को होगा लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 16 दिसंबर को गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने की मंजूरी दी। इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगारों को लाभ होगा।

इस समय देश में करीब पांच करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं और इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है।

किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्हें उनका भुगतान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होता है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है। इससे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में सहूलियत होगी।

सरकार इस उद्देश्य के लिए 3,500 करोड़ रुपये व्यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। शेष राशि, यदि बचेगी तो, उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

इस सब्सिडी का उद्देश्य चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2020–21 के दौरान अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा (एमएईक्यू) के तहत 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा तक चीनी का निर्यात करने पर उसके प्रबंधन, सुधार तथा अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू परिवहन एवं माल भाड़ा शुल्क समेत उस पर आने वाली कुल बाजार कीमत को पूरा करना है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क सेवा 'पीएम वाणी' को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर को टेलीकॉम विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई–फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऐसी कंपनियों से वाई–फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इससे देशभर में सार्वजनिक वाई–फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा।

विशेषताएं

सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क सेवा 'पीएम वाणी' के नाम से जानी जाएगी। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जैसाकि निम्न उल्लेख किया गया है:

- **पब्लिक डेटा आफिस (पीडीओ):** यह केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाई–फाई सेवा स्थलों को स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे।
- **पब्लिक डेटा आफिस (पीडीओ):** यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का काम करेंगे।
- **ऐप प्रदाता:** यह पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे और वाई–फाई वाले हॉट स्पाट इलाकों में ये पीडीओ पीएम वाणी सेवा की उपलब्धता का पता लगाने के बाद उसके अनुरुप ऐप में इसकी जानकारी डालेंगे, ताकि ग्राहक अपने मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकें।
- **सेंट्रल रजिस्ट्री:** यह ऐप सेवा प्रदाता पीडीओ और पीडीओएएस की जानकारी रखेगा। सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव शुरुआती स्तर पर टेलीकॉम विभाग द्वारा किया किया जाएगा।

उद्देश्य

पीडीओ और ऐप प्रदाताओं को इसके लिए अपना कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। ये लोग सरल संचारय (https://saralsanchar-gov-in) वेबसाइट पर टेलीकॉम विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने के सात दिनों के भीतर पंजीकरण हो जाएगा।

सरकार की उपलब्धियां

बैक टू बैक लोन के तौर पर राज्यों को जारी की गई 6,000 करोड़ रुपये की 7वीं किस्त

कानूनी प्रावधानों के साथ सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अब तक कुल 42,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पाटने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की 7वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। इसमें से कुल 5,516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 483.40 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले 3 केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुदुचेरी), जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं, को जारी की गई है। शेष 5 राज्यों– अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम– में जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय की 14 दिसंबर को जारी एक रपट के अनुसार भारत सरकार ने जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में पैदा हुई 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर, 2020 में एक विशेष उधार खिड़की की व्यवस्था की थी। भारत सरकार द्वारा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की ओर से इस खिड़की के जरिए उधार लिया जा रहा है। ये उधारियां 7 चरणों में की गई हैं। अब तक उधार ली गई राशि क्रमशः 23 अक्टूबर, 2020, 2 नवंबर, 2020, 9 नवंबर, 2020, 23 नवंबर, 2020, 1 दिसंबर, 2020, 7 दिसंबर, 2020 और 14 दिसंबर, 2020 को राज्यों को जारी की गई हैं। इस सप्ताह जारी की गई राशि राज्यों को प्रदान की गई ऐसी निधि की 7वीं किस्त थी। इस सप्ताह यह राशि 5.1348% की ब्याज दर पर उधार ली गई है। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 4.7712% की औसत ब्याज दर पर विशेष उधार खिड़की के जरिए कुल 42,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है। जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में हुई कमी को पूरा करने के लिए विशेष उधार खिड़की के जरिए धन प्रदान करने के अलावा भारत सरकार ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पूरा करने के लिए विकल्प–1 का चुनाव करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करने के उद्देश्य से राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50% के बराबर की राशि अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति भी दी है। सभी राज्यों ने विकल्प-1 के प्रति अपनी प्राथमिकता जतायी है। इस प्रावधान के तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50%) की संपूर्ण अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है।

डीआरडीओ हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन

अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश है जहां आकार और परिचालन क्षमता के मामले में इतनी बड़ी सुविधा है

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 दिसंबरए 2020 को डीआरडीओ हैदराबाद में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल ;एचडब्ल्यूटीद्ध परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। यह प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक एचडब्ल्यूटी टेस्ट सुविधा है। अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश है जहां आकार और परिचालन क्षमता के मामले में इतनी बड़ी सुविधा है।

यह सुविधा स्वदेशी रूप से विकसित और भारतीय उद्योगों के साथ की गई साझेदारी का एक परिणाम है। इस सुविधा में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है और यह अत्यधिक जटिल फ्यूचररिस्टिक एयरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर हैदराबाद स्थित डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने मिसाइलए एवियोनिक्स सिस्टमए एंडवांस्ड मैटेरियलए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयरए प्रमुख वितरण प्रौद्योगिकीए निर्देशित ऊर्जा हथियारए गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी क्षमताओं सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से विकसित विभिन्न स्वदेशी प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया।

रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा दो ड्रोन विरोधी तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया। डीआरडीओ युवा वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला. असममित प्रौद्योगिकी ;डीवाईएसएल.एटीद्ध और आरसीआई ने ड्रोन और नवीन एंटी.ड्रोन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया। इसमें मुकाबला करने के लिए ग्राउंड टारगेट और एंटी.ड्रोन एप्लिकेशन को बेअसर करने के साथ.साथ हाई.स्पीड मूविंग टार्गेट सहित कई क्षमताएं शामिल हैं। हथियार प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में सुरक्षित संचार लिंकए प्रभावी पुनरावृत्ति प्रबंधन प्रणालीए उच्च फायरिंग कोणीय संकल्प और दृष्टि.आधारित लक्ष्य पहचान और ट्रैकिंग शामिल हैं।

27 राज्यों ने 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना' का उठाया लाभ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों ने 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' की योजना का लाभ उठा लिया है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 12 अक्तूबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है, जो कोविड-19 महामारी की वजह से कर राजस्व में हुई कमी के कारण इस वर्ष कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस योजना को राज्य सरकारों से बहुत जोरदार प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा अभी तक 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में राज्यों को पहले ही 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जलापूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तीन हिस्से हैं। योजना का भाग-1 पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करता है। इस हिस्से के तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अधिक आबादी और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए असम को इस योजना के तहत 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। योजना का भाग-2 अन्य सभी राज्यों के लिए है, जिन्हें भाग-1 में शामिल नहीं किया गया है। इस भाग के लिए 7500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस राशि का आवंटन इन राज्यों के बीच वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की अंतरिम मंजूरी के अनुरूप केन्द्रीय कर के उनके हिस्से के अनुपात में किया गया है। योजना के भाग-3 का लक्ष्य राज्यों में विभिन्न लोक केन्द्रित सुधारों को बढ़ावा देना है। इस भाग के तहत 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह राशि केवल उन्हीं राज्यों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने सुधार संबंधित अतिरिक्त उधारी अनुमतियों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा 17 मई, 2020 के अपने पत्र में निर्दिष्ट चार सुधारों में से कम से कम तीन सुधार कार्यान्वित किए हैं। ये चार सुधार हैं- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यवसाय करने की सुगमता सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार तथा बिजली क्षेत्र सुधार।

2927 अदालत परिसरों को तीव्र गति वाले वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा गया

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ई–अदालत परियोजना के तहत देशभर के लगभग 2927 अदालत परिसरों को अभी तक तीव्र गति वाले वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) से जोड़ा जा चुका है। परियोजना के तहत 2992 अदालत परिसरों को तीव्र गति डब्ल्यूएएन से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसका 97.86 प्रतिशत हासिल किया जा चुका है। विधि विभाग बीएसएनएल के साथ मिलकर शेष अदालत परिसरों को भी संपर्क मुहैया कराने के काम में संलग्न है।

ई–अदालत परियोजना के तहत विधि विभाग ने विश्व के एक सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क को स्थापित करने की परिकल्पना की थी और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की ई–समिति के साथ मिलकर देशभर के 2992 अदालत परिसरों को तीव्र गति वाले वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था।

इन अदालत परिसरों को ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ), वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल (वीसेट) इत्यादि से जोड़ा जाना था। मई, 2018 में इन सभी परिसरों को मैनेज्ड एमपीएलएसदृवीपीएन सेवा से जोड़ने का कार्य बीएसएनएल को सौंपा गया था, जिसके पास आधुनिकतम स्टेट ऑफ द आर्ट प्रौद्योगिकी के साथ ही अत्याधुनिक दूरसंचार अवसंरचना और ट्रांसमिशन उपकरण हैं और जिसकी देशभर में उपस्थिति है।

ई–अदालत परियोजना के तहत आने वाले बहुत से अदालत परिसर ऐसे दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं जहां संपर्क उपलब्ध कराने के लिए स्थलीय केबल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे इलाकों को तकनीकी तौर पर नहीं जुड़ने योग्य (टीएनएफ) कहा जाता है और विधि विभाग ने इस डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए इन टीएनएफ स्थलों पर आरएफ और वीसेट आदि जैसे वैकल्पिक माध्यमों से संपर्क उपलब्ध कराया।

नगरीय सीमा का विस्तार

यूपी में 28 नई नगर पंचायतों का गठन

(23 नगर निकायों का सीमा विस्तार भी)

यूपी सरकार ने प्रदेश में 28 नई नगर पंचायतों के गठन का फैसला किया है। साथ ही गोरखपुर और वाराणसी नगर निगमों समेत कुल 21 अन्य नगर निकायों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। जिन अन्य नगर निकायों का सीमा विस्तार किया गया है उनमें 9 नगर पालिका परिषद और 12 नगर पंचायतें शामिल हैं। सरकार ने इससे संबंधित प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में नगर निकायों की संख्या 707 से बढ़कर 735 हो गई हैं।

नगर विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक 276 राजस्व गांवों को शामिल करते हुए 28 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। जबकि 77 राजस्व गावों को शामिल करते हुए 12 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है। इसके साथ ही 102 राजस्व गांवों को शामिल करते हुए नौ नगर पालिका परिषदों की सीमा बढ़ाई गई है।

इसी प्रकार नगर निगम गोरखपुर में एक और नगर निगम वाराणसी में नौ राजस्व गांवों को शामिल करते हुए सीमा विस्तार किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में अब नगर निगमों की संख्या 17, नगर पालिका परिषद की संख्या 200 और नगर पंचायतों की संख्या 518 हो जाएंगी।

नई नगर पंचायतों के गठन और पुराने के विस्तार के बाद प्रदेश के शहरी क्षेत्र की जनसंख्या में 905700 और 57474 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 31.16 प्रतिशत शहरी क्षेत्र है। आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में मात्र 22 फीसदी ही शहरी क्षेत्र है। इस हिसाब से यूपी काफी पीछे है। इसे ध्यान में रखकर ही प्रदेश सरकार प्रदेश में शहरीकरण का आंकड़ा बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों ही 20 हजार की आबादी वाले कस्बों में रहने वाले लोगों को भी शहरी सुविधाएं देने के लिए नगर पंचायतों के गठन का फैसला किया था। इसी कड़ी में नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था। जिसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाई गई है।

इन 28 नई नगर पंचायतों का हुआ गठन

रामसनेही घाट (बाराबंकी), खिरौनी-सचित्तागंज व कुमारगंज (अयोध्या), कंचौसी (कानपुर देहात), असोथर (फतेहपुर), ढकवा (प्रतापगढ़), चरवा (कौशांबी), रामगंज (प्रतापगढ़), महमूदपुरमाफी (मुरादाबाद), सूजाबाद (वाराणसी), सैदनगली (अमरोहा), जवां सिंकन्दरपुर, गभाना, टप्पल व बरौली (अलीगढ़), मऊ (चित्रकूट), राजेसुल्तानपुर व जहांगीरगंज (अंबेडकर नगर), कैसरगंज(बहराइच), रटौल (बागपत), रतसड़कला (बलिया), कप्तानगंज, मुंडेरवा व नगर बाजार व गणेशपुर (बस्ती), कलान (शाहजहांपुर), अचलगंज (उन्नाव), चौक (महराजगंज)

इन निकायों के सीमा का हुआ विस्तार

नगर निगम: वाराणसी: वाराणसी नगर निगम की सीमा में 9 राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए सीमा का विस्तार किया गया है। गोरखपुर:- गोरखपुर नगर निगम में एक राजस्व ग्राम को शामिल किया गया है।

नगर पालिका परिषद- नवाबगंज (बाराबंकी) बहराइच, चित्रकूट, कन्नौज, भदोही, जायस (अमेठी), पुखरायां (कानपुर देहात), गौरा बरहज (देवरिया), मारहरा (एटा)।

नगर पंचायते- हरगांव (सीतापुर), परशदेपुर (रायबरेली), औरास (उन्नाव), गोलाबाजार (गोरखपुर), बबेरू, नरैनी व तिंदवारी (बांदा), कुलपहाड़ (महोबा), ओबरा व चोपन (सोनभद्र), हरैया (बस्ती), रामपुरा (जालौन)

नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद के सृजन तथा सीमा विस्तार के फलस्वरूप प्रभावित विकास खण्डों की प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) का आंशिक परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी हैं जबकि ग्राम पंचायत, क्षेत्र एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के निर्धारण के सम्बन्ध में आपात्तिया प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए समय सारिणी निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है

गाँव की सरकार

यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चार चरणों में एक साथ होंगे

(हर वोटर को मिलेंगे 4 मतपत्र)

प्रदेश में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य. क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव इस बार एक साथ होंगे। अभी तक चुनाव आयोग की तैयारियां मार्च 2021 में चुनाव कराने की हैं। आरक्षण का फार्मूला जल्द तय हो जाएगा। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पूर्ण कर ली जाएगी।

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल क्रमश: 25 दिसंबर, 14 जनवरी और 18 मार्च को समाप्त हो रहा है। 25 दिसंबर को आधी रात से ग्राम पंचायतें भंग हो चुकी हैं और प्रशासक नियुक्त हो चुकें हैं। कोविड-19 के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए हैं।

ग्राम पंचायतों में 26 दिसंबर से विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों (एडीओ पंचायत) को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिलाधिकारी और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (ब्लाक प्रमुख) का कार्यकाल पूरा होने पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को प्रशासक तैनात किया गया है।

शासन ने पंचायत चुनावों कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर रखी है। सरकार की मंशा मार्च में पंचायत चुनाव कराने की है जिससे बोर्ड परीक्षाएं समय पर हों। पिछली बार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ हुए थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के चुनाव अलग से हुए थे। इस बार समय बचाने के लिए चारों पदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी की जा रही है।

यानी, एक मतदाता को इस बार चार बैलेट पेपर पर मुहप लगानी होगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर ग्राम प्रधान-ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी-जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग-अलग बूथ बनाए जाएंगे। यानी, प्रत्येक बूथ में वोटर को दो बैलेट पेपर देकर भेजा जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों का आरक्षण फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछली बार क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों का आरक्षण चक्रानुक्रम में किया गया था जबकि ग्राम पंचायतों के आरक्षण की शून्य से शुरुआत हुई थी। इस बार आरक्षण का क्या फार्मूला होगा, यह जल्द ही तय हो जाएगा।

वार्डों का आरक्षण पूरा होने पर शासन इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को देगा। इसके बाद आयोग कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। राज्य सरकार चार चरणों में चुनाव कराना चाहती है। चारों चरण का मतदान मार्च में होगा। कोशिश है कि 31 मार्च तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पंचायतराज विभाग की अभी तक की तैयारियों के मुताबिक फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

आरक्षण फरवरी के तीसरे सप्ताह तक

शासन ने पंचायत चुनाव मार्च में कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर रखी है। आरक्षण का फॉर्मूला जल्द तय हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों का आरक्षण फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछली बार क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों का आरक्षण चक्रानुक्रम में किया गया था। वहीं, ग्राम पंचायतों के आरक्षण की शून्य से शुरुआत हुई थी। इस बार आरक्षण का क्या फॉर्मूला होगा, यह जल्द ही तय हो जाएगा।

वार्डों का आरक्षण पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। राज्य सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पंचायतराज विभाग की अभी तक की तैयारियों के मुताबिक फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में

(उत्तर प्रदेश पुनः प्रथम स्थान पर)

राज्य में समय और पूरी पारदर्शिता से पूरी की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ जनता को मिला तीन नगर निकायों नगर पंचायत मलीहाबाद लखनऊ, नगर पंचायत हरिहरपुर, सन्तकबीर नगर व नगर पालिका परिषद मीरजापुर को भी मिला पुरस्कार

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को एक बार पुनः प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई श्रेणी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों में नगर पंचायत मलीहाबाद लखनऊ प्रथम तथा नगर पंचायत हरिहरपुर, संत कबीरनगर को द्वितीय तथा नगर पालिका परिषद मीरजापुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश को दिए गए। प्रधानमंत्री जी ने छह राज्यों में आरम्भ हुई लाइट हाउस परियोजना (एलएचपी) का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। इसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अवध विहार स्थित परियोजना स्थल पर इसका शिलान्यास किया।

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने उप्र को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किये जाने का स्वागत करते हुए कहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्ग-निर्देशन में उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अव्वल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में योजनाएं समय और पूरी पारदर्शिता से पूरी हो रही हैं, साथ ही इनके समय से पूरा होने से जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं।

नगर विकास मंत्री ने बताया कि लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत लखनऊ के 1040 शहरी गरीबों को 415 वर्गफीट एरिया का फ्लैट अगले वर्ष तक तैयार कर दे दिए जाएंगे। इन आवासों की कीमत का अधिकांश हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जबकि शेष राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी। इन आवासों का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के नियमों के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खुली लॉटरी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सरकार की उपलब्धियां

खरीफ विपणन सीजन 2020-21

90502.23 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ खरीद से 60.67 लाख धान के किसान लाभान्वित

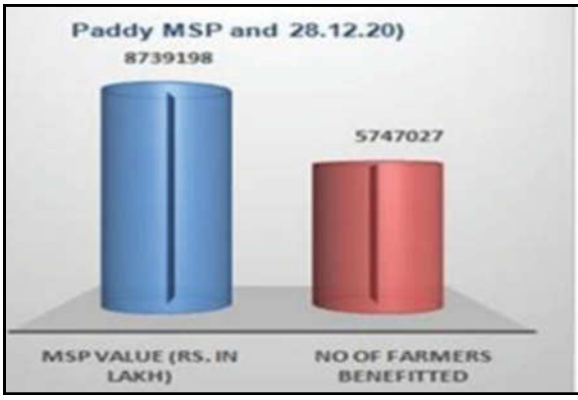

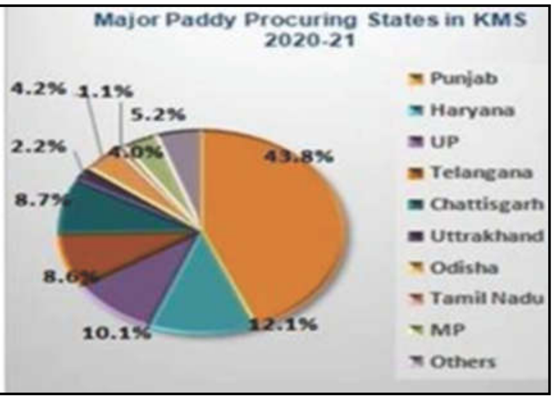

21461.67 करोड़ रुपये मूल्य की 7322391 कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 14,31,227किसान लाभान्वित हुए

वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।

खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 387.15लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष (30.12.2020 तक) 479.35लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में23.81% की वृद्धि दर्ज की गई।479.35लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 42.30% है।

इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा (बारहमासी फसल) की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।

28दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1262.16करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 239845.87मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,29,760किसान लाभान्वित हुए हैं।

इसी तरह, 28दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।

यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021

पिछले 25 साल से आरक्षित जिला और क्षेत्र पंचायत की सीट बदलेगी

उत्तर प्रदेश मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं। इस बार के चुनाव में संभावित प्रत्याशियों बीच सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण की नई व्यवस्था को लेकर है। पूरा गुणा-भाग इस बात को लेकर है कि जो सीट इस समय जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है, इस बार के चुनाव के लिए वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी? इसी के बाद गांव में उम्मीदवार तय होगा। कई संभावित उम्मीदवार अभी तक इसीलिए खुलकर प्रचार नहीं कर रहे हैं. दरअसल उन्हें लगता है कि आरक्षण के ऐलान से पहले की उनकी सारी मेहनत सिर्फ जुआ ही है। पता नहीं वह चुनाव लड़ भी पाएं या नहीं?

वहीं आरक्षण की जो नई व्यवस्था लागू होने की जानकारी है, उसके अनुसार 1995, 2000, 2005, 2010 एवं 2015 के चुनाव में लागू अनुसूचित जाति (एससी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी), ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन क्षेत्रों में इस बार आरक्षण का लाभ लागू नहीं होगा। यही व्यवस्था एससी, एसटी के लिए आरक्षित रहे क्षेत्रों में भी लागू रहेगी। हालांकि ग्राम पंचायत स्तर पर ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, जानकारी अनुसार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य का आरक्षण तय करने में वर्ष 2015 को आधार बनाया जाएगा। यानि उस समय जो ग्राम पंचायत जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस बार उस पर उसका आरक्षण नहीं होगा। प्रस्तावित फार्मूले के अनुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्डों की गणना पहले से तय फार्मूले के अनुसार डीएम के स्तर से की जाएगी। जिला पंचायतों में आगामी सामान्य निर्वाचन के आरक्षण में रोटेशन लागू किया जाएगा।

इस तरह समझें व्यवस्था

25 वर्ष में 1995, 2000, 2005, 2010 एवं 2015 में पंचायत चुनव हुए। इन चुनावों में आरक्षित वर्गों और महिलाओं के लिए रिजर्व जिला पंचायतें इस बार आरक्षित नहीं होंगी। इनमें 'गिरते हुए' क्रम में अगली आने वाली जिला पंचायत से आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि अगर इसके बाद भी रिजर्वेशन कोटा पूरा न हो सके तो पिछले 5 चुनावों में उस वर्ग के लिए आरक्षित जिला पंचायत में फिर से उसी वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण हो सकता है। यही फार्मूला क्षेत्र पंचायत यानि ब्लॉक प्रमुख प्रमुख पद पर लागू हो सकता है।

सबसे पहले जिला पंचायतों को एसटी, एससी और ओबीसी की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर गिरते हुए क्रम में लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद 1995 से 2015 तक आरक्षण की स्थिति देखकर फिर से इन वर्गों के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों के लिए ये व्यवस्था

वहीं 2015 में जो ग्राम पंचायत जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, उस पर उसका आरक्षण नहीं होगा। पिछले साल के आरक्षण से आगे चक्रानुक्रम में सीट तय की जाएंगी। चक्रानुक्रम की शुरुआत एसटी की महिलाओं से फिर एससी, एससी महिलाएं, ओबीसी महिलाएं, ओबीसी के लिए आरक्षित की जाती हैं। यानी कोई ग्राम पंचायत अगर 2015 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी तो इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होगी।

पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम फार्मूला

- पहले एसटी महिला, फिर एसटी महिला/पुरुष
- पहले एससी महिला, फिर एससी महिला/पुरुष
- पहले ओबीसी महिला, फिर ओबीसी महिला/पुरुष

अगर इसके बाद भी महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण पूरा न हो तो महिला इसके बाद अनारक्षित

वैचारिकी

अपनी विचारधारा सहयोग पर आधारित

दीनदयाल उपाध्याय

हम अपने राष्ट्र को परम वैभव की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। या जैसे कि प्रतिज्ञा में कहा गया है कि हम उसकी सर्वांगीण उन्नति देखना चाहते हैं। वैभव की यह अवस्था कैसी होगी? उन्नति की यह स्थिति कैसी होगी? इसकी कुछ कल्पना भी हमने प्रतिज्ञा और प्रार्थना दोनों में करके रखी है। वह अपने धर्म के आधार पर, क्योंकि हमने यह कहा है कि इस धर्म की रक्षा करते हुए हम इसे परम वैभव पर ले जाएं अर्थात् यदि धर्म का विस्मरण कर दिया और यह कल्पना भी कर लें कि हमें किसी भी प्रकार का वैभव प्राप्त हो गया तो हम उसे नहीं मानेंगे।

दूसरी बात जो इससे भी अधिक सत्य है कि राष्ट्र का वैभव बिना धर्म का आधार लिए प्राप्त नहीं हो सकता। बिना धर्म की रक्षा किए वह वैभव नहीं मिल सकता। किसी वस्तु का वैभव उसके धर्म को भुलाकर कभी प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार अपने राष्ट्र के वैभव के संबंध में, इसके साथ ही हमने यह विचार किया था कि जब हम इस धर्म शब्द का उपयोग करते हैं तो उसकी सामान्य कल्पना क्या है? उसके नाते धर्म की जो एक व्याख्या हमने की, उसका आधार यह कि धारणा से धर्म शब्द प्रचलित हुआ था। जिससे धारणा होती है, जिस शक्ति से, जिस तत्त्व से, जिस प्रवृत्ति से, जिस व्याख्या से जिस किसी भी चीज की धारणा हो सके वह धर्म है। प्रजा की धारणा भी होती है और इस नाते से हम किस आधार पर टिके हुए हैं, जब इसका विचार किया तो उसमें यह भी देखा कि शरीर को टिकाए रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक हैं, वह सब धर्म के अंतर्गत आ जाएंगी। समाज कार्य के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, वह समाज धर्म के अंतर्गत आ जाएंगी। समाज और शरीर इन सबको टिकाए रखने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं, वे सब अपने धर्म के, सृष्टि के अंतर्गत आ जाएंगी। इस प्रकार से यह धर्म केवल उसकी एक इकाई है। जो भिन्न–भिन्न इकाइयां हैं, इन सब इकाइयों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। यदि उसके बीच में कोई संघर्ष आ गया, कोई विरोध उत्पन्न हो गया, किसी भी कारण क्यों न हो, विरोध को मिटाकर उसके स्थान पर समन्वय करके धर्म की प्रतिष्ठापना करना, उसके लिए प्रयत्न करना और दोनों प्रकार की इकाइयां, सभी इकाइयां सामान्य आधार के ऊपर अपना विचार प्रकट कर सकें, अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें, एक–दूसरे के साथ पूरकता के भाव से काम कर सकें, वह काम ही वास्तव में धर्म का काम है।

जैसे यदि एक व्यक्ति के शरीर का विचार करते हैं तो शारीरिक दृष्टि से उसकी जो इंद्रियां हैं, वे एक–दूसरे के लिए पूरक हैं। सबका योग्य विकास हो सके, आपस में संघर्ष न आए, वैसे ही एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई संघर्ष न आए और जो व्यक्तियों के समूह बनते हैं, उनके बीच में कोई संघर्ष न आए। विभिन्न प्रकार के बने हुए व्यक्तियों के समूहों के बीच में संघर्ष न आए। संपूर्ण प्राणिमात्र और मानव उनके बीच किसी प्रकार का संघर्ष उपस्थित न हो। संपूर्ण प्राणी जगत् और प्रगति के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष उपस्थित न हो, बल्कि सब एक–दूसरे के लिए पूरकता का भाव लेकर विकास के लिए विचार करते हुए आगे बढ़ें। इस प्रकार की यह स्थिति सामान्य है। हमारा धर्म एकांगी नहीं, वह तो सर्वांगीण है, व्यापक है, सबका विचार करके चलने वाला है। यह हम लोगों का सामान्य विचार रहा है।

अन्य दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में और भी विचार हैं। पश्चिम के भी अनेक विचार हैं। अनेक विचारों के साथ तथा हमारे इस विचार के साथ मूलतः एक मतभेद खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम इस प्रकार से एक इकाई और दूसरी इकाई के बीच सामंजस्य मानकर चलते हैं। परंतु पश्चिम में जो प्रमुख विचार हुआ है, वह यह कि उनके सभी प्रयत्नों में विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य नहीं। वहां उन्होंने विरोध को प्रथम स्थान देकर रखा है। उनकी सामान्य कल्पना संपूर्ण जीवन के संबंध में यह रही है कि मानव का जीवन संघर्षमय है। इस संघर्ष में से ही कुछ पीढ़ियां समाप्त होती चली जाती हैं। बाकी जो हैं, वही प्रगति करती चली जाती हैं। सृष्टि भी इसी संघर्ष के आधार पर खड़ी हुई है। यानी वहां के जीवन में आधार पर विचार करें। अंग्रेजी में एक शब्द को लें तो उनकी संपूर्ण चैपसवेचील ब्वउचमजपजपवद (प्रतिस्पर्धा) के ऊपर आधारित है। यही उनका विचार चलता है। अपनी जितनी भी विचारधारा है, वह सहयोग के ऊपर आधारित है। पूरकता पर आधारित है। यहां पर ब्वउचमजपजपवद का विचार नहीं है। जीवन का आधार ब्–वचमतंजपवद है। सहयोग, सहकारिता आधार है। पूरकता का आधार है, इसको हम मानकर चलते हैं।

वहां इस प्रकार का विचार न करके उन्होंने ब्उचमजपजपवद के विचार को ही प्रमुखता आज भी दी है। दूसरी बात जो उन्होंने विचार किया है वह यह किया है, कि जहां हम प्रत्येक इकाई का विचार उसकी पूर्णता को देखने में करते हैं, वहां उन्होंने इकाई को पूर्णता की दृष्टि से नहीं देखा। उदाहरण के लिए यदि शरीर को लें तो हम व्यक्ति के शरीर को केवल भौतिक आवश्यकताओं का पुंज मात्र मानकर नहीं चलते। भौतिक आवश्यकताओं के साथ–साथ उसकी और कौन–कौन सी आवश्यकताएं भी हैं, उसकी सब प्रकार की हस्तियां हैं। इस वस्तु को मानकर हम चलते हैं, परंतु पश्चिम के अनेक लोग केवल भौतिक दृष्टि से तैयार रहें, जो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसी के संबंध में विचार होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा विचार ही नहीं आता। भौतिक और बाक्ी की आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को प्रमुखता व बाक्ी को गौण स्थान देकर वे चलते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच संघर्ष आते हैं और आ सकते हैं। यह उनका स्वाभाविक और सामान्य विचार है। यदि इस प्रकार के संघर्ष आकर खड़े हो जाते हैं तो वह एक असामान्य स्थिति है। वह धर्म की स्थिति नहीं है, तो एक प्रकार से विकृति की स्थिति है। ऐसा हम विचारकर चलते हैं। जैसे कि अपने दोनों पैर हैं। दोनों पैर भगवान् ने इसलिए बनाए कि वे ठीक प्रकार से चलें। आपस में लड़ते नहीं, टकराते भी नहीं, और दोनों पैरों का उपयोग भी हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। दोनों पैरों में कौन आगे जाएगा और कौन पीछे जाएगा, इसका विचार नहीं करते, झगड़ा भी नहीं होता।

कभी–कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य यदि कमजोर हो गया तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं और जिन पैरों का काम यह है कि मनुष्य के संपूर्ण शरीर के बोझ को संभालकर चलें, जिन पैरों का काम संतुलन बनाए रखना है, वे पैर भी उसके संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ऐसी स्थिति कभी–कभी आती है, परंतु वह स्थिति हमारी कमजोरी के कारण होगी। आहार–व्यवहार में कुछ बिगाड़ से उत्पन्न हुई, किंतु यह सामान्य स्थिति नहीं। यह असामान्य स्थिति है और उस असामान्य स्थिति को दूर करना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए यदि कोई इस असामान्य स्थिति को सामान्य स्थिति कहकर चले और यही सोचकर चले कि पैरों का काम ही लड़खड़ाने का है। पैर लड़खड़ाएं नहीं, इसलिए लकड़ी की पट्टी बांध दें, यदि इस प्रकार का कोई विचार करके चलेगा, तो मूलतरू वास्तव में अलग विचार होगा। ऐसा लगता है कि पाश्चात्य जगत् के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ इसी आधार पर अपने संपूर्ण जीवन की रचना की है और उसमें फिर अपना–अपना स्वार्थ रखकर दोनों के बीच प्रतियोगिता को आधार बनाकर प्रतिदिन बराबर करते गए और उसमें से व्यक्ति और समाज के बीच एक संघर्ष खड़ा किया। पश्चिम के लोग व्यक्ति और समाज के बीच एक संघर्ष खड़ा है, ऐसा मानकर चलते हैं। इसलिए आज वहां पर दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं रू एक ऐसे, जो व्यक्ति को प्रमुखता देकर समाज को पीछे डालकर कहते हैं कि व्यक्ति प्रमुख है। समाज जो कुछ करेगा, व्यक्ति के हितों के लिए करेगा और समाज को वहीं तक मानने को तैयार हैं, जहां तक व्यक्ति के लिए वह सहायक है। इस प्रकार का विचार रखनेवाले लोग पश्चिम जगत् में दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ऐसा विचार रखते हैं कि यदि कुछ व्यक्तियों ने गड़बड़ की तो उस गड़बड़ के आधार पर यह मानकर कि सारे व्यक्ति खराब हैं और यह व्यक्ति समाज के संबंध में विचार नहीं कर सकते, ये लोग दूसरों के हित का विचार नहीं कर सकते, इसलिए इनकी सत्ता को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। वे समाज को ही प्रमुख स्थान देकर जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानकर चलते हैं, व्यक्ति को मान का स्थान दिया तो समाज समाप्त हो जाएगा। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यदि समाज को प्रमुखता दी, व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज का हितदृये दोनों मानो साथ नहीं चल सकते। दोनों में से हमें एक को चुनना पड़ेगा। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए तो समाज के हित की चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज के हित की सोचने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में समाज को समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार का विचार करनेवाले लोग वहां पर पैदा हो गए।

वे सही विचार नहीं करते हैं। मानव और बाकी के अन्य प्राणियोंदृइन सबके बीच मानो एक प्रकार का संघर्ष है। संघर्ष में मानव को अधिकार है, सभी अन्य प्राणियों का उपयोग अपने लिए करे। अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई है, केवल शक्ति की होड़ है। डार्विन ने विचार किया और कहा कि यहां पर नतअपअंस है। जो योग्य हैं, वही ठीक क्रम में हैं, बाक्ी जितने अयोग्य हैं, एक–दूसरे को खाते चले जाते हैं। अपने जीवन को बनाए रखने की लड़ाई और इस लड़ाई में संघर्ष ही इसका प्रमुख आधार है। कुछ और आगे विचार करते चले जाएं तो यह देखेंगे कि उनकी दृष्टि में मनुष्य और प्राणियों के बीच तथा मनुष्यों में संपूर्ण मानव समाज, छोटे–छोटे गुट हैं, राष्ट्र हैं और राष्ट्रों में और राष्ट्र और व्यक्तियों के बीच में, व्यक्ति की भी जो अनेक प्रकार की हस्तियां हैं, उन सबके बीच में मानो एक परमानेंट संघर्ष की स्थिति है।

क्रमशः

–संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : हरिगढ़ (5 जून 1962)

विशेष : मकर संक्राति माघ स्नान

नवजीवन बोध करने वाला वैदिक पर्व

मकर संक्रांति ऐसा ही एक वैदिक पर्व है जो हमारे लौकिक जीवन को देवजीवन की ओर मोड़ता है। सूयोर्पासना का यह पर्व हमें प्रबोधित करता है कि हम जड़ता व आलस्य त्याग कर स्फूर्तिवान बनें। यह ऋतु पर्व हमारे भीतर नवजीवन का बोध भरकर हमें चैतन्य, जागृत व जीवंत सक्रिय बनाता है। जानना दिलचस्प है कि समूचे विश्व में भारत की ज्ञान ध्वजा लहराने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति के दिन ही 12 जनवरी को हुआ था।

एकमात्र सूर्य ही ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो सतत क्रियाशील रहकर हम धरतीवासियों का भरण पोषण करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषिगणों ने सूर्य को विराट पुरुष की संज्ञा दी है। हमारे यहां सूर्य की उपासना विविध रूपों में आदिकाल से होती रही है।

वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि सूर्य ऊर्जा व संवेदना का सघनपुंज है।। पुराणकार कहते हैं कि जब दिवाकर मकरस्थ होते हैं, तब सभी समय, प्रत्येक दिन एवं सभी देश व स्थान शुभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ मुहर्त में सूर्यदेव का सामीप्य पाकर हमारी धरती माता आलदित हो उठती हैं। समूची प्रकृति में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है।

इस दिन तीर्थराज प्रयाग एवं गंगासागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। शास्त्रकार कहते हैं कि इस दिन सूर्योपस्थान के उपरांत यज्ञ में दिए। हव्य व दान को ग्रहण करने देवगण धरती पर आते हैं। मकर संक्रांति यानी पृथ्वी पर जीवंतता व जागृति का शुभारंभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन देवलोक में भी दिन का आरंभ होता है। इसलिए इसे देवायन भी कहा जाता है। इस दिन देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर दान-धर्म और जप-तप करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन स्नान का भी बेहद महत्व है। आज के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मकर संक्रांति बेशक एक खगोलिया घटना है, लेकिन यह हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।

दिलचस्प तथ्य है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं पारसी, इस्लाम व ईसाई धर्म में भी सूर्य को चेतना का केंद्र माना गया है। आल्लामा इकबाल ने आफताब की स्तुति के रूप में गायत्री मंत्र का बड़ा सुंदर अनुवाद उर्दू में किया है। ईसाई धर्म में भी रविवार का दिन पवित्र घोषित कर इस दिन आराधना व दान को पवित्र फलदायी बताया गया है।

वैदिक मान्यता के अनुसार इस दिन से खरमास (पौष माह) के समापन के साथ रुके हुए विवाह, मुंडन, गृह निर्माण आदि मंगल कार्य पुन: शुरू हो जाते हैं। यह स्नान पर्व मूल रूप ऋतु चक्र परिवर्तन और नई कृषि उपज से जुड़ा है। सूर्यदेव की कृपा से धरतीमाता हम सबके भरण- पोषण के लिए अपनी कोख से नवान का उपहार देती हैं। इसी खुशी में हमारे अन्नदाता मकर संक्रांति का पर्व मनाकर भगवान सूर्य को धन्यवाद देने के साथ उनसे अनुकंपा का आशीर्वाद मांगते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में जितने रूप इस त्योहार को मनाने के प्रचलित हैं, उतने किसी अन्य पर्व के नहीं। कहीं लोहड़ी, कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल, कहीं संक्रांति और कहीं उत्तरायणी। उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व मुख्य रूप से खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है।

श्रद्धांजलि

नहीं रहे विचारक माधव गोविंद वैद्य

(11 मार्च, 1923 – 19 दिसंबर, 2020)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ विचारक और संगठन के प्रथम प्रवक्ता श्री माधव गोविंद वैद्य (बाबूराव) का 19 दिसंबर को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 11 मार्च, 1923 को जन्मे श्री वैद्य को 'संघ का विश्वकोश' के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने संगठन को विश्व के सामने एक बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया। श्री वैद्य देश के संस्कृत भाषा के विद्वानों में शुमार थे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत कम जीवित लोगों में से एक थे, जिन्होंने संघ के सभी छह सरसंघचालकों के साथ काम किया। उन्होंने एक सक्रिय, सार्थक और प्रेरक जीवन जीया। वे आठ साल में ही संघ के स्वयंसेवक बन गए तथा 95 वर्ष की आयु तक शाखा में भाग लेते रहे।

शोक संदेश

श्री माधव गोविंद वैद्य के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक शोक संदेश में कहा कि संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान, उत्तम पत्रकार, विधान परिषद के सक्रिय सदस्य, उत्कृष्ट साहित्यिक, ऐसी सारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बाबूराव जी ने यह सारी गुण संपदा संघ में समर्पित कर रखी थी। वे संघ कार्य विकास के सक्रिय साक्षी रहे। उनका जीवन व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा आजीविका इन चतुर्विध आयामों में संघ संस्कारों की अभिव्यक्ति करने वाला संघानुलक्षी, संपन्न व सुंदर गृहस्थ जीवन था। सरल भाषा में तर्कशुद्ध रीति से व अनुभूतिमूलक विवेचन से संघ को अपनी वाणी और लेखनी द्वारा वे जगत में सर्वत्र प्रस्तुत करते रहे। संघ ने शोक संदेश में कहा कि श्री वैद्य जी का पूरा परिवार आज एक विस्तृत छत्रछाया का अभाव अनुभव कर रहा है। हम सबका तथा उनका सांत्वन करना कठिन है। समय ही उसका उपाय है। बाबूराव जी का जीवन हम सबको हर अवस्था में अपने कर्तव्य पालन का कार्य अविचल और अडिग रीति से करना सिखा रहा है।

श्री वैद्य के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि श्री एमजी वैद्य जी एक प्रतिष्ठित लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने दशकों तक संघ में व्यापक रूप से योगदान दिया। उन्होंने भाजपा को मजबूत करने के लिए भी काम किया। उनके निधन से दुःखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते कहा कि श्री एमजी वैद्य ने मां भारती की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे जीवनपर्यंत सामाजिक समरसता तथा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रयासरत रहे। उनका जाना संपूर्ण समाज के लिए अपूरणीय क्षति है।

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का निधन

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद श्री सत्यदेव सिंह का 17 दिसंबर को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। खराब स्वास्थ्य के कारण उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

श्री सत्यदेव सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

उन्होंने 1980 से 1985 तक भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। वह सादगी और पारदर्शी राजनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भाजपा केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

उन्होंने 1977 में पहली बार गोंडा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में वे 1991 और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। राम मंदिर आन्दोलन में भी देवीपाटन मंडल से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

अवध क्षेत्र बैठक

युवा उद्यमी सम्मान युवा मोर्चा

बतकही कार्यक्रम बाराबंकी

अयोध्या कार्यक्रम

सीतापुर पंचायत चुनाव बैठक

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2018-20
जनवरी प्रथम 2021 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 11–13 (प्रथम पाक्षिक)

महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में प्रदेश अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी